(ख) क्या वर्ष 1980-81 के लिये प्राय: सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्र कार्यक्रम और मरुस्थल विकास कार्यक्रम के लिये किया गया धन का आवंटन वर्ष 1978-79 और 1979-80 में किये गये आवंटन की तुलना में कम है और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार का विचार इस अकाल समस्या का स्थानीय समाधान और मरुस्थलीय क्षेत्रों का विकास कितने वर्षों में करने का है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) :** (क) जी नहीं । केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अप्रैल, 1974 से मार्च, 1979 तक सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के लिए केवल 50 प्रतिशत सहायता दी गई थी। 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान जम्मू तथा काश्मीर और हिमाचल प्रदेश के शीत शुष्क क्षेत्रों में मरुभूमि विकास कार्यक्रम के लिए शतप्रतिशत सहायता दी गई थी । वर्ष 1977-78 के दौरान राजस्थान, गुजरात तथा हरियाणा के गर्म शुष्क क्षेत्रों को सभी योजनाओं के लिए शत प्रतिशत सहायता दी गई थी और वर्ष 1978-79 के दौरान वनरोपण तथा चरागाह, पशुपालन, डेरी, भूजल विकास तथा जल संचयन योजनाओ के लिए कृषि, बागवानी तथा ग्रामीण विद्युतीकरण क्षेत्र में व्यय को केन्द्र तथा राज्यों द्वारा बराबर-बराबर के आधार पर वहन किया गया था ।

(ख) केवल मरुभूमि विकास कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता का अनुपात 1 अप्रैल, 1979 से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया था । यह निर्णय राज्य सरकारों को निधियो का अधिकाधिक हस्तातरण के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के लिए वर्ष 1980-81 हेतु किए गए धन के आवंटन 1979-80 के दौरान किए गए आबंटनो के बराबर है । तथापि, वर्ष 1980-81 के लिए किये गये निधियों के आवंटन कुछ राज्यों में 1980-81 में कम बजट प्रावधानो और विभिन्न जिलो में "अन्तर्गत लाये गये क्षेत्र की सीमा" से अन्तर्गत लाए गये "खंडों की संख्या" में निधियों के आवंटन के आधार में परिवर्तन होने की वजह से वर्ष 1978-79 के दौरान किए गये बजट प्रावधानो से कम हैं ।

(ङ) मरुभूमि क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं । यद्यपि इन क्षत्रों के पूर्व विकास के लिए अपेक्षित वर्षों की संख्या का पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता है फिर भी चल रही योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से मरुभूमि क्षेत्रो में लोगों के आय स्तरों और उनके जीवन स्तर में अवश्य ही सुधार होगा ।

**Guidelines for New Sugar Units**

6753. SHRI B. V. DESAI:
SHRI P. M. SAYEED:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the new guidelines issued by the Union Government for new sugar units have not made much impact on the sugar production and as well as its price decrease;

(b) if so, to what extent these guidelines will be advantageous to the sugar units;

(c) how many new sugar units were set up after new guidelines were issued; and

(d) the areas where they have been set up?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) The guidelines recently issued were for licensing of new sugar factories

during the Sixth Five Year Plan as a long term measure for increasing the production of sugar in future years. Since the establishment of a newly licensed sugar factory takes a couple of years before it goes into production the mere announcement of new guidelines is not likely to have any immediate impact either on sugar production or on prices.

(b) The guidelines will be helpful to the entrepreneurs for the preparation and submission of applications for grant of licence for setting up new sugar units.

(c) No new sugar unit has been set up after new guidelines were issued on 4th July, 1980.

(d) Does not arise.

**Participants at Moscow Olympics**

6754. SHRI S. B. SIDNAL: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) the number of sportsmen visiting U.S.S.R. for participation in the Olympic Games;

(b) the number of non-sportsmen officials visiting U.S.S.R. to attend the Games;

(c) the number of Indians allowed to go to U.S.S.R. to watch the Games as spectators; and

(d) the nature and amount of assistance and other encouragement given to the various sportsmen participating in the Olympic Games?

THE MINISTER OF EDUCATION AND HEALTH AND SOCIAL WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): (a) and (b) A 94 member contingent proceeded to Moscow for participation in the XXII Olympic Games. Of the 94 members contingent, there were 75 sportsmen|competitiors and 19 officials including Chief-de-Mission, Assistant Chief-de-Mission, Managers, Coaches of the teams etc.

(c) Information is not available with the Ministry.

(d) The travel costs of the sportsmen and concerned officials are borne by the Government. This may amount to Rs. 10 lakhs approximately. Government also arranged coaching camps for the participants in collaboration with the National Institute of Sports.

**Adult Education Centres in Orissa**

6755. SHRI CHINTAMANI JENA: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) the number of adult education centres under the National Adult Education Programme that have been recommended by the Orissa Government for Central Government's approval; and

(b) the number of centres which have been approved by the Central Government?

THE MINISTER OF EDUCATION AND HEALTH AND SOCIAL WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND):